मजदूरों का पलटवार, दोषी खुद हमें ही फटकारते हैं....

पेज दो का शेष

कुछ लोग भाषण देंगे और दूसरी तरफ़ सिर्फ़ सुनने वाली भीड़. ये बात मुझे मंज़ूर नहीं है. सब को बोलना है. भाषण नहीं, अपनी बात कहो, जैसे अपने साथी मज़दूरों से करते हो. वही बात असली बात होती है. अगर कोई ज़िद करके बैठा है कि नहीं बोलूँगा, उसे भी कोई ना कोई सवाल ज़रुर पूछना है, जो इस वक़्त उसके ज़हन में हैं." उनके जोर देने के बाद ही सुभाष व रवि ने अपनी बातें रखीं, जो इस सभा के सबसे महत्वपूर्ण भाषण बने. साथ ही कई लोगों ने अपने सवाल भी रखे. मज़दूर तहरीक़ में एकता के महत्त्व को रेखांकित करते हुए, उन्होंने कहा कि जब आज़ाद नगर की गुडिया पर हुए ज़ुल्म के ख़िलाफ़ आन्दोलन चरम पर था, उसी वक़्त कुछ लोगों ने उन लोगों के साथ मिलकर एक 'संयुक्त समिति' बनाई, जो दिल से मज़दूर आन्दोलन के साथ नहीं थे. उसी से आन्दोलन कमज़ोर हुआ. कहाँ गई अब वह 'संयुक्त समिति'? किसी को उस समिति के नाम भी मालूम हैं क्या?

क्रांतिकारी मज़दूर मोर्चा के अध्यक्ष कॉमरेड नरेश ने अपने ज़ोरदार वक्तव्य में बताया, कि 7 नवम्बर (तत्कालीन रुसी कैलेंडर के हिसाब से 25 अक्तूबर) 1917 इतिहास में एक ख़ास महत्त्व रखता है. अपने महान नेता, कॉमरेड लेनिन के नेतृत्व में रूस के मज़दूरों और मेहनतक़श मज़दूरों ने, उस दिन वह कर दिखाया था, जिसे समझाने में सर्वहारा के महान नेता, कार्ल मार्क्स और फ्रेडेरिक एंगेल्स ने अपना जीवन न्यौछावर किया था. जैसा कि प्रतिष्ठित अमेरिकी पत्रकार, जॉन रीड ने अपनी कालजयी पुस्तक में लिखा है, उन दस दिनों में सचमुच दुनिया हिल उठी थी. मज़दूर सत्ता हांसिल कर सकते हैं, सारी दुनिया की घेराबंदी के बावजूद उसे महफ़ूज़ रख सकते हैं, दुनिया यकीन नहीं कर पा रही थी. 7 नवम्बर मज़दूरों का सबसे बड़ा त्योहार है, यही है हमारी 'होली-दीवाली-ईद और क्रिसमस'.

हमारा गौरवशाली इतिहास हमें बार-बार पढ़ना चाहिए. उससे सीखना चाहिए जिससे हम अपनी अठन्नी-चवन्नी की ज़द्दोज़हद से ऊपर उठकर, अपनी असल मुक्ति का रास्ता और सही रणनीति ढूंढ सकें. सारा निर्माण, सारा उत्पादन मज़दूर और मेहनतक़श किसान करते हैं, और वे ही आज सबसे कठिन जीवन जीने को मज़बूर हैं. दूसरी तरफ़ मुट्ठीभर थैलीशाह दौलतों के पहाड़ों पर बैठे हैं. ये स्थिति अब और नहीं चलने वाली. क्रांतियों को रोका नहीं जा सकता. ये पूंजीवादी व्यवस्था भुखमरी और बेरोज़गारी के सिवा कुछ नहीं दे सकती.

आज़ाद नगर आन्दोलन के हर कार्यक्रम में अपनी सक्रीय उपस्थिति दर्ज़ कराने वाले, साथी बाबूलाल जी ने दो अहम सवाल किए थे; 'रूस में समाजवादी राज क़ायम होने के इतने साल बाद भी, पूंजीवाद कैसे पुनर्स्थापित हो गया और सारा उत्पादन मज़दूर ही करते हैं, सारे उत्पादन के मालिक मज़दूर ही हैं; आप लोग ऐसा कैसे कह सकते हैं, मालिक कच्चा माल लाता है, मशीनें लगाता है, अपनी पूंजी लगाता है?' कॉमरेड सत्यवीर सिंह ने अपने वक्तव्य में संक्षेप में इन सवालों का जवाब देने का प्रयास किया. अभी तक जितनी भी क्रांतियाँ हुई हैं; दास प्रभुओं के विरुद्ध दास वर्ग का विद्रोह अथवा सामंतों के ख़िलाफ़ किसानों की बग़ावत, उनमें, समाज के एक क़िस्म के अल्पसंख्यक लुटेरों की जगह, दूसरी क़िस्म के अल्पसंख्यक लुटेरों ने सत्ता संभाली है. सत्ता से खदेड़े गए लुटेरों को, सत्ता में प्रस्थापित हुए लुटेरों में रूपांतरित होने का अवसर, हर बार मिला. इसीलिए वर्ग संघर्ष भी इतना तीखा नहीं हुआ. पूंजीवाद को ध्वस्त कर, सर्वहारा वर्ग द्वारा सत्ता हांसिल करने के लिए जो क्रांतिकारी संघर्ष होगा, वह पहली ऐसी क्रांति होगी, जिसमें बहुसंख्यक सर्वहारा वर्ग, मेहनतक़श किसान वर्ग के साथ सत्ता संभालेगा. साथ ही, सरमाएदार लुटेरों को उनका 'साम्राज्य' बचाने, छुपाने का कोई अवसर नहीं मिलेगा.

मुकेश अम्बानी हो या गौतम अडानी; रोटी खानी है तो फैक्ट्री के गेट पर, ट्रेड यूनियन प्रतिनिधि के सामने काम के लिए रिपोर्ट करना होगा, भले उस फैक्ट्री के मालिक वे ख़ुद भी क्यों ना रहे हों. उनके ज़हन से उनके 'लूट के पहाड़' आसानी से नहीं जाते. मध्यम वर्ग की भी, समाजवादी सत्ता के विरुद्ध षडयंत्रकारी गतिविधियों में शामिल होने की उपजाऊ ज़मीन बहुत दिनों तक बनी रहती है. कई रंग-ढंग के 'ख्रुश्चेव और देंग' काफ़ी दिनों तक 'मज़दूर' और क्रांतिकारी होने का दिखावा करते रहते हैं, कम्युनिस्ट पार्टियों में ऊपर खिसकते रहते हैं. जहाँ तक दूसरे सवाल; सारे उत्पादन पर मज़दूरों के मालिकाने का सवाल है, कच्चा माल भी या तो क़ुदरत का दिया हुआ है, या फिर वह मज़दूरों-किसानों की श्रम शक्ति से ही पैदा होता है. मशीनों को भी, किसी दूसरे कारखाने में, मज़दूर ही बनाते हैं. 'पूंजी' क्या है? मज़दूरों के श्रम का वह हिस्सा, जिसे मालिक ने हड़प लिया, जिसका भुगतान मज़दूरों को नहीं हुआ. इसीलिए, फैज़ अहमद फैज़ के शब्दों में, "ये सारा माल हमारा है, हम सारी दुनिया मांगेंगे".

सभा के बाद, आज़ाद नगर बस्ती में, ज़ोरदार नारे लगाते हुए मज़दूरों का जुलूस भी निकला. महान रुसी समाजवादी क्रांति को याद करने के साथ ही, सभा का मक़सद, मासा के आह्वान पर आगामी 13 नवम्बर को होने जा रही, 'आक्रोश रैली' के प्रति अपनी एकजुटता/ सॉलिडेरिटी रेखांकित करना भी था. इसलिए प्रमुख नारे थे- लेबर कोड रद्द करो, मज़दूरों के अधिकारों पर हमला नहीं सहेंगे, न्यूनतम दिहाड़ी 1,000/ रु देनी होगी, न्यूनतम मासिक वेतन 27,000/ रु देना होगा, मज़दूरों की हत्यारी ठेका प्रथा रद्द करो, महान रुसी क्रांति अमर रहे, सर्वहारा के महान नेता कॉमरेड लेनिन को लाल सलाम, इंक़लाब जिंदाबाद, पूंजीवाद-साम्राज्यवाद- फासीवाद हो बर्बाद.

सबसे अंत में लखानी के पीड़ित मज़दूरों की एक सभा हुई. सभा में, उनके जो भी भुगतान लेने बाक़ी हैं, उनका दावा दाखिल करने के फॉर्म बांटे गए, कैसे भरना है यह बताया गया, ताकि 14 नवम्बर की अगली तारीख पर श्रम कार्यालय में जमा किया जा सके. मज़दूरों का जो भी हिसाब 'लखानी फुटवेयर प्रा लि' से होना बाक़ी है, किसी भी मद में मज़दूरों का जो भी पैसा लेना बनता है, उसे हांसिल करने का संघर्ष, उसके अंजाम तक पहुँचने तक, ज़ारी रखने के दृढ निश्चय के साथ मज़दूर सभा संपन्न हुई.

खट्टर की बॉन्ड नीति के विरोध में मेडिकल छात्र उतरे संघर्ष पर

डॉक्टरों से करायेंगे सेवा और खट्टर खायेंगे मेवा

दाखिला प्रक्रिया ठप्प, पुराने छात्र उतरे संघर्ष पर, सेवारत डॉक्टर, एचसीएमएस एसोसिएशन तथा आईएमए भी समर्थन में आए

करनाल/ रोहतक/ नूंह (म.मो.) 'जब बोलो झूठ बोलो, बार-बार झूठ बोलो, जोर-जोर से झूठ बोलो' संघ के इसी गुरूमंत्र को आत्म-सात कर चुके इसके पूर्व प्रचारक मनोहर लाल खट्टर इसका पूरी बेशर्मी से इस्तेमाल कर रहे हैं। राज्य के मेडिकल कॉलेजों में दाखिला लेने वाले जो छात्र पहले 80 हजार रुपये वार्षिक के हिसाब से साढ़े चार साल के कोर्स के लिये 3 लाख 60 हजार रुपये बतौर फीस अदा करते थे अब खट्टर सरकार उनसे 10 लाख रुपये वार्षिक के हिसाब से 45 लाख फीस मांग रही है।

अपने-आप को बहुत चतुर और नीट द्वारा चयनित मेडिकल छात्रों को बेवकूफ समझने वाले खट्टर, सीधे-सीधे 10 लाख फीस न कह कर 80 हजार बतौर फीस और 9 लाख 20 हजार बतौर बॉन्ड मनी मांग रहे हैं। योग्यता एवं मेरिट के आधार पर चयनित छात्र जब दाखिला लेने खट्टर के पांच कॉलेजों में पहुंचे तो उनसे कहा गया कि वे पहले 10-10 लाख जमा करायें, तभी उनसे आगे की बात की जायेगी। छात्रों ने इस पर असमर्थता जतायी तो उन्हें 15 दिन का समय दे दिया गया। लेकिन छात्र इसके लिये भी तैयार नहीं हैं और वे इस नीति के विरुद्ध संघर्ष पर उतर गये हैं।

समझने वाली बात यह है कि यहां पर बॉन्ड शब्द का इस्तेमाल ही गलत किया जा रहा है। बॉन्ड का अर्थ होता है कि डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करने के बाद बने डॉक्टरों को हरियाणा सरकार की नौकरी अनिवार्य रूप से करनी होगी। इसका उल्लंघन करने वाले डॉक्टरों को बॉन्ड मनी सरकार को देना होगा। यानी कि खट्टर सरकार की नौकरी करने से इनकार करने की स्थिति में ही बॉन्ड मनी के रूप में पूरे 45 लाख सरकार को देने होंगे। इस शर्त को मानने के लिये सभी छात्र तैयार हैं लेकिन खट्टर नहीं मान रहे क्योंकि उनके पास डॉक्टरों के लिये रिक्त स्थान तो बहुत हैं परन्तु वे इसके वेतन पर अपना पैसा 'बर्बाद' नहीं करना चाहते।

समझने के लिये ईएसआई कार्पोरेशन के मेडिकल कॉलेजों के बॉन्ड को देखा जा सकता है। यहां पर एक लाख वार्षिक के हिसाब से पूरे कोर्ष की फीस मात्र 4 लाख 50 हजार है। बॉन्ड के मुताबिक यहां से निकलने वाले डॉक्टरों को एक साल तक ईएसआई कॉर्पोरेशन की नौकरी करनी होगी। उल्लंघन करने की स्थिति में 10 लाख रुपये कॉर्पोरेशन में जमा कराने होंगे। इसके चलते लगभग तमाम छात्र बॉन्ड के अनुसार बल्कि बॉन्ड अवधि से भी अधिक समय तक कॉर्पोरेशन की नौकरी कर रहे हैं।

अपनी इस घोर जन विरोधी नीति को उचित ठहराने के लिये वे एक से एक मूर्खतापूर्ण तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं। वे कहते हैं कि राज्य में 28 हजार डॉक्टरों की जरूरत हैं जबकि यहां केवल 6 हजार कार्यरत हैं। इसके लिये उन्हें राज्य के हर ज़िले में मेडिकल कॉलेज खोलने के लिये पैसे की जरूरत है, इसलिये वे मेडिकल छात्रों से यह 'बॉन्ड मनी' वसूलने जा रहे हैं।

यहां सवाल यह उठता है कि खट्टर सरकार ने बीते आठ साल में कितने मेडिकल कॉलेज बनाये? एक भी नहीं। छांयसा के निकट मोठूका स्थित अटल बिहारी मेडिकल कॉलेज बीते चार-पांच साल से इनके कब्जे में है, जो इन्हें बना-बनाया कौड़ियों के भाव मिल गया। उसी को चलाने में इनके मुंह से झाग निकल रहे हैं। खट्टर पर सवाल यह भी बनता है कि बीते आठ साल में जो दो लाख करोड़ का कर्ज उन्होंने राज्य के सिर पर चढ़ा दिया है, उससे कहां गुलछर्रे उड़ाये?

शेष जो चार कॉलेज ये चला भी रहे हैं वे भी फैकल्टी एवं साजो सामान के आभाव में चलने की बजाय घिसट भर ही रहे हैं। 90 प्रतिशत सरकारी सहायता से चलने वाला अग्रोहा मेडिकल कॉलेज अब भी पहले की तरह ही दो लाख वार्षिक फ़ीस ले रहा है। विदित है कि पूरी तरह से शिक्षा ब्यापारियों द्वारा चलाये जा रहे मेडिकल कॉलेज मात्र 12 लाख वार्षिक फीस लेते हैं जबकि जमीन खरीदने से लेकर बिल्डिंग बनाने तक का सारा खर्चा उन्हें अपने पल्ले से करना पड़ता है।

दूसरा सवाल ये बनता है कि राज्य में जब 22 हजार डॉक्टरों की कमी वे खुद मान रहे हैं तो उन्हें इसे दूर करने के लिये डॉक्टरों की भर्ती करने में क्या तकलीफ है? यदि उनकी नीयत साफ़ हो तो प्रति वर्ष उनके कॉलेजों से निकलने वाले 600 डॉक्टरों को वे भर्ती कर सकते हैं। परन्तु इसके लिये तो उनके पास पैसा ही नहीं हैं, कर दाता का सारा पैसा तो घोटालों व अय्याशियों की भेंट चढ़ जाता है।

पीजी छात्रों से भी साढ़े सात लाख वार्षिक मांगे

विदित है कि एमबीबीएस करने के बाद पीजी (पोस्ट ग्रेजुएशन) के लिये नीट द्वारा अति मेधावी छात्रों को चुना जाता है। ये डॉक्टर पढ़ाई के साथ-साथ अपने प्रोफेसरों की निगरानी में डॉक्टरी का अभ्यास भी करते हैं। पढाई और डॉक्टरी में लगे इन डॉक्टरों की स्थिति लगभग बंधुआ मज़दूरों जैसी हो जाती है। इसके लिये इन्हें बाकयदा एक लाख से अधिक वेतन भी मिलता है। अब खट्टर जनाब इन पीजी छात्रों से भी साढे सात लाख रुपये वार्षिक वसूलने की फिराक में हैं, मानो इसी से अपना खजाना भरेंगे।

इतना ही नहीं एमबीबीएस के जो छात्र दूसरे, तीसरे, व चौथे वर्ष में चल रहे हैं उनसे भी खट्टर इसी हिसाब से फीस मांग रहे हैं। खट्टर की इस नीति के विरोध में राज्य के तमाम सरकारी कॉलेजों में दाखिला प्रक्रिया ठप्प हुई पड़ी है। तमाम कॉलेजों में छात्र सड़कों पर उतर कर प्रदर्षन कर रहे हैं।

इस सबके बावजूद अपनी हठधर्मी के चलते राज्य के रोहतक स्थित स्वास्थ्य विश्वविद्यालय में पांच नवम्बर को हुए दीक्षांत समारोह में जा पहुंचे। इसके लिये खट्टर ने पुलिस बल के द्वारा छात्रों पर लाठी चार्ज करवाया, पानी की बौछार करवाई और तो ओर रात को ढाई बजे तमाम प्रदर्शनकारी छात्र-छात्राओं को पुलिस हिरासत में करवा दिया। इसके बावजूद भी तमाम छात्रों के हौंसले बुलंद हैं। उन्हें तमाम सामाजिक एवं राजनीतिक सगठनों की ओर से पूरा सहयोग एवं समर्थन मिल रहा है। इसका एक परिणाम स्पष्ट दिख रहा है, खट्टर पूरी मेडिकल पढ़ाई का सत्यानाश करने पर तुले हैं।